साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 16-22 जनवरी , 2023, वर्ष-8, अंक-40

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मध्यप्रदेश में सांची और एसबीआई के समन्वय का दिखा असर

किसान हो रहे आत्मनिर्भर

» केन्द्रीय मुद्रा ऋण योजना अंतर्गत किसानों को त्रिपक्षीय अनुबंध

भोपाल। जागत गांव हमार

एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एमपीसीडीएफ) भोपाल ने सितंबर 2022 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने के उद्देश्य से सांची और एसबीआई के समन्वय से मुद्रा ऋण देन का एमओयू निष्पादित होने से दुग्ध व्यवसाय में अपने मजबूत कदम बढ़ाने वाले पशुपालकों में प्रसन्नता दिखाई देने लगी है।

उल्लेखनीय है कि एमपीसीडीएफ भोपाल के अंतर्गत संचालित सभी 06 सहकारी दुग्ध संघ द्वारा सांची और एसबीआई के समन्वय प्रयास से संबंधित संघ अंतर्गत समिति सदस्यों को बैंक शाखाओं द्वारा राशि निरंतर विमुक्त करवाई जा रही है। वर्तमान में मुद्रा ऋण के मामले देखें तो एमपीसीडीएफ से संबद्ध प्रदेश के 06 सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से 10941 समिति सदस्यों ने 31188 दुधारू पशु क्रय करने के आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 4306 आवेदन स्वीकृत हुए हैं और इनमें से 370 प्रकरणों में 128 पशु क्रय करने के लिए 608 लाख की राशि एसबीआई ने वितरित की है। मुद्रा ऋण लेने वाले किसानों के समूहों द्वारा अन्य राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि से दुधारू पशुओं को क्रय जा रहे है।

नाबार्ड के द्वारा ऋण प्रदान करने की उपलब्ध कराई गई सुविधा

मुद्रा ऋण के मुख्य बिंदु

» भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा ऋण योजना अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराई गई सुविधा।

» सांची और एसबीआई के समन्वय से मुद्रा ऋण से लाभांवित करने किसानों के द्वार पहुंच रही एसबीआई।

» मुद्रा ऋण लेने वाले किसान दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनने दिखाई दे रहे अग्रणी।

» एसबीआई किसानों का दस्तावेजीकरण कर प्रक्रिया को सुगम बनाने कर रहे अनूठा प्रयोग।

» ग्रामीण दुग्ध उत्पादक किसानों में मुद्रा ऋण योजना के प्रति दिखाई दे रही खुशियां।

» मुद्रा ऋण लेने वाले किसानों को राज्य के बाहर से पसंदीदा दुधारू क्रय करने की स्तंत्रता।

» किसानों के समूहों द्वारा मुद्रा ऋण लेकर राज्य के बाहर यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि से दुधारू पशुओं को कर रहे क्रय।

» मुद्रा ऋण योजना अंतर्गत दुधारू पशुओं को क्रय करने के पहले और बाद में किसानों को किया जा रहा प्रशिक्षित।

» प्रशिक्षित किसानों को क्रय किए गए दुधारू पशुओं को पोषण करने में होगी आसानी और अत्याधिक दुग्ध उत्पादन करने सांची के पोष्टिक पशुआहार से कराया जा रहा अवगत।

» एमपीसीडीएफ से संबद्ध सभी सहकारी दुग्ध संघों की है 7000 दुग्ध सहकारी समितियां, समितियों में हैं, 246000 दुग्ध उत्पादक है सदस्य, प्रतिदिन 09 लाख लीटर दूध किया जाता है संकलित।

» केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयास से किसानों को मुद्रा ऋण से आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को किसान दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में होते जा रहे आत्मनिर्भर।

भारत सरकार की मुद्रा ऋण योजना अंतर्गत एमपीसीडीएफ भोपाल के दिशा-निर्देशन में एसबीआई के माध्यम से दुग्ध समिति स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को पशु उत्प्रेरण के लिए ऋण वितरण एक सराहनीय पहल है।

रवीन्द्र पाटिल, डीजीएम, एलएचओ, एसबीआई भोपाल

सांची और एसबीआई के समन्वय से समिति सदस्यों को मुद्रा ऋण देकर योजना अंतर्गत राज्य के बाहर से किसान अपने मन पसंद के पशु क्रय करके आना प्रारंभ हो गए हैं, भविष्य में इसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।

-गोविंद अहिरवार, एजीएम, एलएचओ, एसबीआई भोपाल

एमपीसीडीएफ भोपाल के अंतर्गत संचालित सहकारी दुग्ध संघों एवं एसबीआई के मध्य निष्पादित एमआयू के अंतर्गत किसानों को दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाने की पहल के निश्चित रूप से सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।

आरके दूर्वार, महाप्रबंधक, एमपीसीडीएफ, भोपाल

सांची और एसबीआई के समन्वय से केंद्र और राज्य सरकार की मंशानुसार मुद्रा ऋण हमारे घर पर एसबीआई बैंक आकर दे रही है, दुग्ध उत्पादन व्यवसाय में किसान आत्मनिर्भर बन रहे है।

-यशपाल रामसिंह, समिति सदस्य दुग्ध शीत केंद्र मंदसौर, जिला उज्जैन

मुद्रा ऋण मिलने से अपने मनपसंद के पशुओं को राज्य के बाहर से क्रय करने की स्वतंत्रता है। दुग्ध उत्पादन में किसानों का कार्य मजबूत कदम है। किसानों की आय में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादन व्यवसाय एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है।

-भूपेन्द्र सिंह, समिति सदस्य दुग्ध शीत केन्द्र रतलाम, जिला उज्जैन

जीआई टैगिंग से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को मिलेगी नई पहचान

» प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा

» समिट में जीआई टैगिंग के लिए हुआ त्रि-पक्षीय अनुबंध

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्थानीय उत्पाद जीआई टैगिंग के माध्यम से अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने नाम से जाने-पहचाने जा सकेंगे। इसके लिए इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भारत शासन, वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाईल कमेटी, मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम तथा नाबार्ड के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध हुआ। लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव की उपस्थिति में यह अनुबंध हुआ। अनुबंध पर एमडी नाबार्ड निरूपम मेहरोत्रा, अपर सचिव मप्र शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग मनोज खत्री, प्रबंध संचालक मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव और टेक्सटाईल कमेटी की ओर से श्री तपन राऊत ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव कुटीर एवं ग्रामोद्योग मनु श्रीवास्तव और टेक्सटाईल कमिश्नर भारत सरकार रूप राशि भी उपस्थित थीं। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जीआई टैगिंग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय शिल्पकारों और बुनकरों के उत्पादों को नई पहचान और राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध हो सकेगा। अनुबंध के अनुसार टेक्सटाईल कमेटी द्वारा जीआई टैगिंग के लिए उत्पादों का चिन्हांकन एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा। नाबार्ड इन उत्पादों के लिए वित्तीय व्यवस्था करेगा। स्थानीय शिल्पियों के साथ समन्वय स्थापित कर मप्र के उत्पादों का संरक्षण और प्रचार-प्रसार करेगा।

नांदना प्रिंट-पंजादरी को मिलेगा जीआई टैग

इन्वेस्टर्स समिट के दौरान तारापुर जिला नीमच के नांदना प्रिंट एवं जोबट जिला अलीराजपुर की पंजादरी को जीआई टैगिंग प्रदान करने के प्रस्ताव पर टेक्सटाईल कमेटी भारत सरकार और मप्र संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा हस्ताक्षर किए गए। साथ ही प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके रिटेल चाय आउटलेट चाय सुट्टा बार और प्रजापति समाज के मध्य अनुबंध किया गया। सुट्टा बार की ओर से अभिनव दुबे, पूरनलाल प्रजापति और हेमंत प्रजापति ने हस्ताक्षर किए।

इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया, कम लागत में बढ़ेगी आमदनी

अब गोबर से चलेगा टी-7 ट्रैक्टर, किसानों की होगी बचत

भोपाल। जागत गांव हमार

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया है। यह ट्रैक्टर बेनामन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दावा किया जा रहा कि इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आम ट्रैक्टर की ही तरह होगी। साथ ही प्रदूषण भी कम करेगा। इस ट्रैक्टर के लिए करीब 100 गायों के गोबर को एकत्र कर बायोमीथेन में बदला गया है। गाय के गोबर से आपने खाद और पेंट बनते सुना होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपने ईंधन के तौर पर होते हुए नहीं देखा होगा। किसान तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब गोबर की मदद से कृषि यंत्रों को चलाया जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ट्रैक्टर तैयार किया जा चुका है, जो गोबर से चलेगा। इसका नाम टी-7 है।

टी-7 ट्रैक्टर में क्रायोजेनिक टैंक लगाया गया है। यह ईंधन की तरलता बनाए रखेगा। क्रॉयोजेनिक टैंक 160 डिग्री के तापमान में बायोमीथेन को लिक्विफाइड करता है। गोबर से बने इस ईंधन से 270 बीएचपी का ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर में पाई जाने वाली मिथेन गैस का इस्तेमाल ट्रैक्टर को चलाने में किया है। यह ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार सीएनजी गैस का उपयोग कर हम गाड़ियां चलते आ रहे हैं।

ट्रैक्टर में क्रायोजेनिक टैंक

ट्रैक्टर की खासियत दरअसल, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया है। यह ट्रैक्टर बेनामन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दावा किया जा रहा कि इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आम ट्रैक्टर की ही तरह होगी। साथ ही प्रदूषण भी कम करेगा। इस ट्रैक्टर के लिए करीब 100 गायों के गोबर को एकत्र कर बायोमीथेन में बदला गया है।

किसानों के खर्चे में कटौती

किसानों को ये ट्रैक्टर मिलने के बाद उनके अतिरिक्त खर्च में भी कटौती की जाएगी। अतिरिक्त खर्च में कटौती के चलते किसान बची हुई राशि का इस्तेमाल फसल की बेहतरी के लिए कर सकेगा। इससे उपज भी बढ़ेगी और किसानों को मुनाफा भी बढ़ेगा। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर के पूर्व-उत्पादन मॉडल का एक वर्ष के लिए परीक्षण किया गया था। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कॉर्नवाल काउंटी में एक खेत में परीक्षण के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन केवल एक वर्ष में 2,500 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन तक कम हो गया था।

कटनी, जबलपुर, सागर के बाद सीधी में मामला आया सामने

मप्र के खरीदी जा रही अमानक धान

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में इनदिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से अमानक और मिलावटी धान की खरीदी कर सरकार को चपत लगाई जा रही है। कटनी, जबलपुर, सागर के बाद अब कटनी में अमानक धान खरीदने का मामला सामने आया है। जिले के धान खरीदी केंद्र बघवार में धान की बोरियों में भूसी, बालू व पत्थर मिलने की शिकायत मिली है। इसके बाद उमाकांत उमराव प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल एवं कलेक्टर सीधी ने एक संयुक्त जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच टीम ने धान खरीदी केंद्र बघवार एवं स्लोक गोदाम रामपुर में रखी अमानक धान का परीक्षण किया, जिसमें 13 प्रतिशत धान अमानक पाई गई। धान की बोरियों में धान की भूसी, बालू, पत्थर भी पाए गए।

जानकारी के अनुसार भोपाल एवं सीधी के जांच दल ने पहले स्लोक गोदाम रामपुर नैकिन में रखी धान का परीक्षण किया। इसके बाद हनुमते महिला स्वयं सहायता समूह धान खरीदी केंद्र बघवार की पाई गई अमानक धान का परीक्षण किया। इसके बाद धान खरीदी केंद्र बघवार पहुंचकर वहां रखी धान का परीक्षण किया। इसमें 13 प्रतिशत धान अमानक पाई गई एवं धान के बोरों में धान की भूसी, पाए गए।

बोरियों का वजन 30 से 33 किलो मिला

यही नहीं, भेजी गई धान का वजन भी काफी कम पाया गया। कई-कई बोरियों का वजन 30 से 33 किलो मिला। इस कारण उक्त खरीदी केंद्र से अब तक भेजी गई धान में 95 क्विंटल धान कम है। धान खरीदी केंद्र बघवार में अमानक पाई गई धान का परीक्षण करने भोपाल, सतना एवं सीधी के विशेषज्ञों की टीम धान खरीदी केंद्र बघवार से गोदाम रामपुर नैकिन में रखी धानों का परीक्षण किया। अमानक की सीमा पांच प्रतिशत तय की गई है, जबकि यहां 13 प्रतिशत धान अमानक पाई गई। अधिकांश धान कार्बनिक मापदंड एक प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत, अकार्बनिक एक प्रतिशत के स्थान पर 5.5 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित एवं घुने दाने पांच प्रतिशत के स्थान पर 13 प्रतिशत, अपरिपक्व कुम्लाहे एवं सिकुड़े दाने तीन प्रतिशत के स्थान पर 7.2 प्रतिशत अमानक पाए गए।

धान में बालू पत्थर की भी शिकायत

शासन द्वारा प्रत्येक गोदामों में धान खरीदी केंद्रों से गोदामों में आने वाली धान के बोरों के वजन एवं मानक परीक्षण के लिए सर्वेयर नियुक्त किया गया है। सर्वेयर धान की बोरियों का परीक्षण कर जो धान मानक एवं जिन बोरियों का वजन निर्धारित मात्रा में पाया जाता है, उन्हीं धान की बोरियों को गोदाम के अंदर रखा जाता है। जो धान अमानक पाई जाती है अथवा जिन बोरियों का सही वजन नहीं होता धान की भूसी, रेत एवं छोटे पत्थर भी खरीदी केंद्र बघवार एवं स्लोक गोदाम उन्हें वापस खरीदी केंद्रों को भेज दिया जाता है। धान में बालू पत्थर की शिकायत पर की गई जांच नीलेश शर्मा प्रभारी अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सीधी ने बताया कि धान खरीदी केंद्र बघवार में धान अमानक पाए जाने एवं धान की बोरियों में बूसी, बालू एवं पत्थर पाए जाने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार संबंधित व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र करेगा 3 नए सहकारी संगठनों का निर्माण

सहकारिता से समृद्ध होंगे किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

देश का सहकारिता क्षेत्र सीधा ग्रामीण क्षेत्र और किसानों, कृषि के उत्पादन और किसानों की आमदनी से जुड़ा है। इसी क्षेत्र से अब किसानों को और लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 सहकारी संगठनों को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सरकार ने साल 1982 में को-ऑपरेटिव एक्ट और साल 1987 में ट्राइफेड बनाया था। इस तरह 35 साल के लंबे इंतजार के बाद अब नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल लेवल को-ऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेशनल मल्टी स्टेट सीड को-ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। सहकार से समृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने इन 3 संस्थाओं का गठन करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय और सरकार के पूरे सहयोग से किसानों की उपज को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सपोर्ट करने का प्लान है। साथ ही उपज की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। देश में 8 लाख 50 हजार पंजीकृत सहकारिता संघ है, जिसमें करीब 29 करोड़ से मेंबर है। इन सदस्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से और किसान ही है।

जैविक उत्पादन की काफी क्षमता

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश में जैविक उत्पादन की काफी क्षमता है, जिसे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए नेशनल लेवल को-ऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर से किसानों को उत्पादन क्षेत्र के नजदीक ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनमें सस्ती दरों पर जैविक उत्पादों की जांच, सर्टिफिकेशन और तकनीकी सहयोग देना शामिल है। इससे किसानों को अपने जैविक उत्पादों की सही मार्केटिंग और उचित दाम हासिल करने में भी मदद मिलेगी। वहीं नेशनल मल्टी स्टेट सीड को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किसानों को सीड का उत्पादन और बिक्री, बीज बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

ऑनालइन पेमेंट से जुड़ेंगे किसान

हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई इंसेटिव स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम , अन-ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ-साथ किसान और मजदूरों तक ले जाना संभव हो पाएंगा. इस स्कीम के लिए भी केंद्र सरकार ने 2,600 करोड़ मंजूर किए हैं।

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटिड से भी मदद

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटिड नामक नई संस्थागत सोसाइटी के जरिए भी ट्रेडिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, के साथ-साथ किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी गाइडेंस दी जाएंगी. इस संगठन के जरिए सरकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को भी सहकार से जोड़ा जाएगा।

20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत वनक्षेत्र हो गया है खराब

अब नर्मदा के आस-पास रह गया 38 प्रतिशत वनक्षेत्र

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र की लाइफलाइन नर्मदा नदी के कैचमेंट में सिर्फ 38 प्रतिशत ही वनक्षेत्र रह गया है। इसमें भी 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत वनक्षेत्र खराब हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान होशंगाबाद और निमाड़ के खंडवा व इंदौर में हो रहा है, जबकि डिंडोरी में 38 हजार हेक्टेयर बिगड़े वनों का सुधार हुआ। विशेषज्ञ नर्मदा के कैचमेंट में वन क्षेत्र घटना सही नहीं मान रहे हैं। इसीलिए सालों बाद इस बार राज्य सरकार नर्मदा के कैचमेंट (जलग्रहण क्षेत्र) में ही 1.32 करोड़ पौधे लगाने जा रही है।

इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से होगी जो 31 जुलाई तक चलेगी। इसके अलावा भी सवा दो करोड़ पौधे वन विभाग और लगाएगा। इस बार वन समितियों के साथ स्थानीय लोगों व सभी विभागों को साथ जोड़ा जा रहा है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार 18 हजार 406 हेक्टेयर में ये पौधे लगाए जाने हैं। नर्मदा के कैचमेंट में पिछले कुछ सालों में कितना वनक्षेत्र कम हुआ है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। यहां बता दें कि नर्मदा नदी का कुल कैचमेंट 98,796 वर्ग किमी है। इसमें से मप्र के हिस्से में 85,149 वर्ग किमी क्षेत्र आता है जो 87 प्रतिशत है। इसी में 32 हजार 400 वर्ग किमी (38 प्रतिशत) फॉरेस्ट एरिया है।

नर्मदा के मुहाने लगे यूकेलिप्टस

वर्ष 1970-80 के दौरान 400 हैक्टेयर क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए गए थे। इन्हें अब हटाया जा रहा है। दो सौ हेक्टेयर के यूके लिप्टस काट दिए गए हैं। बाकी भी इस साल कटेंगे। इसके बदले में साल, सागौन, आंवला, महुआ, अचार, हर्रा और स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त एपीसीसीएफ ललित सूद का कहना है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने 1985 से 2005 तक नर्मदा पर बने बांधों के डूब क्षेत्र के बदले वैकल्पिक पौधरोपण किया। यह आज भी बेहतर है। लेकिन तब जरूरत के मुताबिक राशि खर्च नहीं हसे पाती थी। नर्मदा के कैचमेंट में वन विभाग अब पौधे लगा रहा है तो यह अच्छी चीज है। वैसे केंद्र सरकार की गाइड लाइन कहती है कि जहां कुल क्षेत्र का 33 फीसदी वन क्षेत्र है तो वह बेहतर स्थिति है, लेकिन नर्मदा के कैचमेंट में फॉरेस्ट एरिया पूरी तरह जंगल से भरा होना अच्छा होगा।

पूरी दुनिया में मोटे अनाजों से जोड़कर कई आयोजन किए जा रहे

मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए चयन

बाजरा, रागी, कुटकी, संवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो को शामिल किया गया

भोपाल। जागत गांव हमार

वैसे तो दुनिया में मिलेट की 13 वैरायटी मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 अनाजों- बाजरा, रागी, कुटकी, संवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो को शामिल किया गया है। भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल-2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। अब पूरी दुनिया में मोटे अनाजों से जोड़कर कई आयोजन किए जा रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ राज्य सरकारें किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं तो वहीं लोगों को थाली तक इसे पहुंचाने के लिए भी जागरुकता किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। खासतौर पर शहरों में गेहूं और चावल ज्यादा प्रचलन में है। ऐसे में लोगों की थालियों तक 8 प्रकार के पोषक अनाजों को पहुंचाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है। इस चुनौती को आसान बनाने के लिए मिलेट के प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये फूड प्रोडक्ट उन 8 मोटे अनाजों से बनाए जाएंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए चिन्हित किया गया है। पोषण से भरपूर इन्हीं 8 मोटे अनाजों की जानकारी देंगे।

बाजरा| बाजरा एक सबसे ज्यादा उगाए और खाए जाने वाला मोटा अनाज है, जिसकी सबसे ज्यादा खेती भारत और अफ्रीका में की जाती है। बाजरा को कई इलाकों में बजरी और कंबु के नाम से भी जानते हैं। बाजरा को हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए बाजरा की फसल वरदान है। इससे मोटे दानों को अलग करने के बाद पशु चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बाजार के फसल अवेशेषों से जैव ईंधन भी बनाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड समेत कई न्यूट्रिएंट से भरपूर इस मिलेट से ब्रेड, दलिया, कुकीज समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं।

रागी| रागी को देसी भाषा में नचनी भी कहते हैं। इस अनाज का रंग लाल-भूरा और स्वाद अखरोठ जैसा होता है। रागी को भी सूखा और कम पानी वाले इलाकों में उगाया जा सकता है। यह अनाज हर तरह की मिट्टी में पैदा होकर भी प्रोटीन विटामिन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन-बी जैसे कई गुणों से भरपूर होता है। इसके नियमित सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रैशर जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज भारत के साथ-साथ पूरे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में रागी की खेती की जा रही है।

कंगनी| कंगनी को एशियाई देशों में उगाया जाता है। इस मिलेट का दाना पीला होता है, जिसे दलिया से लेकर पुलाव जैसे कई व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कम बारिश वाले इलाकों में उगने वाली कंगनी प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। कंगनी का स्वाद भी काफई हद तक अखरोठ की तरह ही होता है।

चेना| चेना एक ऐसा मोटा अनाज है, जो पूरी दुनिया में उगाया जाता है। भारत के साथ-साथ यूरोप, चीन और अमेरिका में इससे सूप, दलिया और नूडल बनाए जाते हैं। यह मिलेट फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है. साथ ही, चेना प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-बी, आयरन और जिंक समेत कई विटामिन और खनिजों का मेन सोर्स है।

सांवा| सांवा को देश के अलग-अलग इलाकों में ऊडालू या झंगोरा के नाम से भी जानते हैं। सांवा का इतिहास भी बाकी मोटे अनाजों की तरह हजारों साल पुराना है। इसमें मौजूद पोषक तत्व-फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन-बी आदि शरीर को खास एनर्जी देते हैं। इसके नियमित सेवन से सूजन, हार्ज डिजीज और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। किसान भी सावां उगाना बेहद पंसद करते हैं, क्योंकि इसमें कीट या बीमारियां लगने का खतरा नहीं रहता।

ज्वार| मिनरल, प्रोटीन, विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयरन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर ज्वार के दानों को लोग भूनकर खाते हैं। ज्वार के आटे से बना काजल आंखों को ठंडक देता है और कई रोगों को भी दूर करता है। खांसी -जुकाम होने पर ज्वार के दानों को गुड़ में मिलाकर खाया जाता है।

कुटकी| कुटकी के ज्यादातर गुण चेना से मिलते हैं. इसकी खेती करना किसानों के लिए जितना आसान है, इसके सेवन से भी उतने फायदे होते हैं। कुटकी की फसल 65 से 75 दिनों में पक जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने में कुटकी को असरदार माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।

कोदो| कोदो एक पारंपरिक अनाज है, जिसे केद्रव भी कहते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर कोदो के दाने काफी छोटे है, लेकिन इसकी फसल धान की तरह ही लगती है। लाल भूरे रंग के कोदो के दानों में कैंसर, मधुमेह औप पेट के रोग दूर करने की शक्ति है ही। इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

ई-नाम 22 राज्यों की मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म

कृषि मंत्रालय की ई-नाम पहल ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता

1.74 करोड़ से अधिक किसान और 2.39 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत

नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय की एक प्रमुख पहल ई-नाम ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार-2022 में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. एन विजय लक्ष्मी, संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2022 प्रदान किए हैं। ई-नाम 22 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1260 एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ताकि 203 कृषि और बागवानी जिंसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ई-नाम मंडी प्रचालनों के डिजिटल परिवर्तन और कृषि जिंसों के ई-ट्रेडिंग को अभिप्रेरित कर रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक, 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 2.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 69 मिलियन मीट्रिक टन का कुल व्यापार दर्ज किया गया है।

नागरिकों को सशक्त बना रहा

ई-नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) के लॉन्च के साथ, एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया गया है जो कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में व्यक्तिगत सेवा प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। ई-नाम किसानों के लिए बेहतर मूल्य की खोज के लिए संचालन में आसानी, पहुंच, पारदर्शिता और संचालन की दक्षता के माध्यम से डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बना रहा है।

सात श्रेणियों में दिया अवॉर्ड

डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा अभिनव डिजिटल समाधान/ अनुकरणीय पहल को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वावधान में एमईआईटीवाई द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स (डीआईए) की स्थापना की गई है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्टअप्स को भी डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 को 07 विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रदान किया गया।

किसान आज जमा कर सकते हैं आवेदन

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम में किसानों को मिलेगा पुरुस्कार

भोपाल। मप्र में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए जाने है जिसके चलते कृषकों को 16 जनवरी तक आवेदन जमा करने को कहा गया है। ये पुरस्कार अपनायी गई कृषि तकनीकी, उपज एवं उत्पादकता के आधार पर दिया जाएंगे। इसके लिए जिले के इच्छुक कृषक व कृषक समूह से आवेदन आमंत्रित किए जाना है।

किसानों को कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा परियोजना) के तहत वर्ष 2021-22 की गतिविधियों के आधार पर कृषक पुरस्कार एवं कृषक समूह पुरस्कार के लिये अपनायी गई कृषि तकनीकी, उपज व उत्पादकता के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। इस के लिए इच्छुक कृषक व कृषक समूह से आवेदन आमंत्रित किए गए है। जिला व विकासखण्ड स्तरीय समितियों के मूल्यांकन व अनुशंसा पर 25 हजार रुपए प्रदान किया जाएगा, जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 5 विभिन्न कृषि क्षेत्र (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी) के एक-एक कृषक को समिति की अनुशंसा एवं मूल्यांकन के आधार पर 10 हजार रुपए का विकासखण्ड स्तरीय पुरूस्कार एवं विभिन्न कृषि क्षेत्र (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी) के एक-एक कृषक समूह को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 20 हजार रुपए का कृषक समूह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। अब कृषक आवेदन जमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक कार्यालय में 16 जनवरी की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा करा सकेगे। जिन कृषकों को पूर्व 10 वर्षों में पुरस्कार मिल चुका है वे आवेदन नहीं करेंगे।

मप्र में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं

निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फसलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया हैं जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मध्यप्रदेश को फ़ूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला है।

प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिर्च, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूँ का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है।

राज्य का कृषि-जलवायु क्षेत्र 11 भाग में विभक्त है। इससे कृषि उपज में विविधता दिखायी देती है। प्रदेश में 10 प्रमुख नदी घाटियाँ और 0.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले अंतर्देशीय जल निकाय, 17 हजार किलोमीटर से अधिक फैली हुई नदियां और नहरें, 60 हजार हेक्टेयर से अधिक छोटे-बड़े तालाबों से पानी की भरपूर उपलब्धता से राज्य में कृषि उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है।

मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूँजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खाद्य प्र-संस्करण: मप्र सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिये भी कई कार्य किये जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्मलाइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही हैं। उत्पादक सहकारी समितियां और सहकारी समितियां अपनी संपूर्ण मूल्य श्रंखला के साथ सूक्ष्म उद्यमों को सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

वर्ष 2021 में दुनिया के खाद्य प्र-संस्करण बाजार का आकार 5.7 ट्रिलियन था। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 7.60 प्रतिशत की कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया प्रशांत इस क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। भारत, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया जैसे उभरते बाजार तेजी से वैश्विक विकास को गति देंगे। बढ़ते ग्राहक आधार के करीब होने के लिए विनिर्माण और प्र-संस्करण तेजी से इन बाजारों में जायेंगे। भारत का खाद्य उत्पादन उद्योग 400 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। यह वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचेगा। भारत की विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन में एक मजबूत स्थिति है और

इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों के चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया है।

इस परिदृश्य में मध्यप्रदेश, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग को सशक्त बनाने के लिये लगातार काम कर रहा है। राज्य में 8 स्थान पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भण्डारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहाँ 3 लाख 54 हजार वर्गमीटर की कुल सीमा के साथ एक विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने फूड इनोवेशन हब विकसित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है। राज्य में पहले से ही 5 प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो इस क्षेत्र के लिए मूल्य श्रृंखला में मौजूदा कार्य बल को शिक्षित करने और प्रतिभाशाली कौशल बल जोड़ने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार के प्रोत्साहनों के ईतर भी प्रोत्साहनों से उद्योगों को आकर्षित कर रही है।

मध्यप्रदेश ने हाल के दिनों में कैडबरी, आईटीसी, यूनिलीवर जैसी दिग्गज नामी कम्पनियों को शासन स्तर से अनुकूल नीतिगत बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर निवेश को आकर्षित किया है। मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग समर्थक नीतियां बनायी हैं। वित्तीय मोर्चे पर, खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन का डेढ़ गुना है। राज्य ने अपने निर्यात को वर्ष 2005-06 में 83 करोड़ रुपये मूल्य के 9 हजार 600 मीट्रिक टन से बढ़ा कर वर्ष 2021-22 में एक हजार 300 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग एक लाख 43 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पादों को 18 प्रतिशत से अधिक के आश्चर्यजनक सीएजीआर के साथ बढ़ाया है।

एक जिला-एक उत्पाद योजना में मप्र ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आँवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदर्श बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं।

राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों की जलवायु और क्षमताओं के आधार पर किसानों को ऐसी उपज लगाने के लिये प्रोत्साहित किया है जिससे रस, जैम, स्क्वैश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, आवश्यक तेल, लुगदी, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम जैसे प्र-संस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है।

खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के अलावा, डेयरी गतिविधियां मप्र की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वर्तमान में तरल दूध का हिस्सा राज्य के कुल बाजार हिस्सेदारी का 48 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6 प्रतिशत का योगदान है।

यदि भूमि पड़ी है व्यर्थ, तो भी कमा सकते हैं अर्थ

डॉ. वेद प्रकाश सिंह
वरिष्ठ प्रशिक्षक, सेडमैप, भोपाल

कई बार हम बेकार पड़ी भूमि को बेकार ही पड़े रहने देते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि बेकार पड़ी भूमि का उपयोग कैसे करना है। कुछ लोग तो यह सोचकर बेकार पड़ी भूमि का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह घाटे का सौदा लगता है, परंतु अब नई कृषिकरण तकनीक से हम बेकार पड़ी भूमि से भी लाभ पा सकते हैं। जिनके पास नहीं है वह भी किसी और से बेकार पड़ी भूमि लीज पर लेकर नई तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।

यहां हम जानेंगे कि बेकार भूमि कितने प्रकार की हो सकती है और उनसे कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें आंकड़ों पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा। बेकार पड़ी भूमि से लाभ की संभावनाएं इसलिए भी अधिक हैं क्योंकि अपने देश में 1,69,96,000 हेक्टेयर जमीन बंजर है। यह भी कह सकते हैं कि ये भूमि खेती योग्य नहीं है। जुलाई में लोकसभा में प्रस्तुत कागजात बताते हैं कि देश के पांच राज्यों में सर्वाधिक बंजर जमीन है, इनमें गुजरात (25.52 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (24.03 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (17.27 लाख हेक्टेयर) और मप्र (13.57 लाख हेक्टेयर) भूमि अनुपयोगी है। हालांकि सरकार द्वारा बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं परंतु जनभागीदारी एवं जनजागरूकता के बगैर इस कार्य में जल्द सफलता मिलती नहीं दिखती।

हमें देश में बंजर पड़ी भूमि पर औषधीय सगंधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहित करना होगा। किसानों के पास अथवा गांवों में पड़ी अनुपजाऊ भूमि, जलप्लावित भूमि, बंजर भूमि, छायादार भूमि, पड़ती भूमि, दलदली भूमि पर औषधीय सगंधीय पौधों की खेती की जा सकती है, जिससे किसान अथवा इच्छुक युवा इस प्रकार की कृषि को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें तथा उनके पास उपलब्ध ऐसी भूमि जिसपर वे परंपरागत खेती करने में असमर्थ हैं, उनका भी विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए ऐसी भूमि पर भी खेती कर लाभ कमा सकें, जैसे अनुपजाऊ भूमि, जलप्लावित भूमि, बंजर भूमि, छायादार भूमि, पड़ती भूमि और दलदली भूमि आदि का उपयोग कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

इन भूमियों पर प्रमुख औषधीय पौधे जैसे सफेद मूसली, सतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ आदि और सगंधीय पौधे जैसे मेन्था, लेमनग्रास, पामारोजा, सिट्रोनेला, गुलाब, जामा रोजा, गेंदा आदि के कृषिकरण का कार्य किया जा सकता है। अब जल भराव अथवा दलदली वाली भूमि को ही ले लीजिए। इस पर पांच तरह की खेती हो सकती है। इस भूमि पर बच, मंडूकपर्णी, ब्रम्ही, खस और नागरमोथा की खेती की जा सकती है। जलप्लावित भूमि पर सिंघाड़ा, मखाना की खेती की जा सकती है। छायादार भूमि पर अधिकांश औषधीय-सगंधीय पौधों को पसंद है इसलिए इस भूमि पर सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, सर्पगंधा, कालमेघ, हल्दी, अदरक, सूरन (ओल या जिमीकंद) घृतकुमारी (ग्वारपाठा) आदि की खेती की जा सकती है। पड़ती भूमि पर ऐसे पौधों की खेती की जा सकती है जो अधिक पीएच मान पर भी उत्पादन दे सकते हैं, जैसे पामारोजा, जामारोजा खस इत्यादि। अनुपजाऊ या बंजर भूमि पर घृतकुमारी की फसल सबसे उपयुक्त है।

औषधीय सगंधीय फसलों की बाजार में अच्छी मांग के कारण इन फसलों की खेती परंपरागत फसलों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभकारी है। औषधीय सगंधीय पौधों पर प्रशिक्षण पाने का लाभ यह होगा कि इससे परंपरागत खेती की तुलना में प्रति एकड़ आमदनी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इन फसलों की बुवाई तथा कटाई-गहाई का समय परंपरागत फसलों की बुवाई, कटाई-गहाई से अलग होता है।

औषधीय सगंधीय फसलों के प्रसंस्करण से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सगंधीय फसलों में एक खास प्रकार की गंध होने के कारण आवारा मवेशियों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की संभावना भी अल्प होती है। इस कारण औषधीय एवं सगंध फसलों की खेती कृषकों के लिए अधिक लाभदायक है। कृषि को लाभदायी बनाने की दिशा में अपनाए जा रहे प्रमुख कदमों में यह कदम भी किसानों की आय वृद्धि में सहायक हो सकता है। यदि हम वाकई कृषि लागत में कमी, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विविधीकरण, उत्पाद का बेहतर मूल्य और कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर संकल्पित होकर कार्य करने के लिए संकल्पित हैं तो हमें बंजर भूमि पर खेती की योजना को मूर्तरूप देना ही होगा।

प्रदेश में सहकारिता से हो रहा उन्नति का पथ प्रशस्त

प्रदेश में सहकारिता से उन्नति का पथ प्रशस्त हो रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिये शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के साथ समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूँ, धान आदि फसलों का उपार्जन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग में विभिन्न क्षेत्रों में रजिस्टर्ड समितियाँ स्थानीय स्तर पर नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री की किसानों के हित में शुरू की गई अनेक योजना में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना से किसानों को सूदखोरों और ब्याज के कुचक्र से मुक्ति मिल रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में साल दर साल बढ़ोत्तरी हो रही है। ऋण उपलब्धता में वर्ष 2021-22 में वर्ष 2019-20 की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में 11 हजार 471 करोड़ रूपये का ऋण किसानों को वितरित किया गया था, जबकि वर्ष 2021-22 में 16 हजार 807 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 14 हजार 700 करोड़ से अधिक के ऋण का वितरण किया जा चुका है। किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहकारी समितियों का उल्लेखनीय योगदान है। प्रदेश में 4 हजार 534 पैक्स सामान्य सुविधा केन्द्रों से किसानों को केसीसी पर (किसान क्रेडिट-कार्ड) कृषि ऋण और खाद-बीज का वितरण सुनिश्चित कर रही हैं। पैक्स से वर्ष 2020-21 में 10 लाख 85 हजार क्विंटल और वर्ष 2021-22 में 10 लाख 3 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को दिया गया। प्रदेश में संगठित क्षेत्र के कुल बीज उत्पादन का 80.15 प्रतिशत सहकारी बीज संस्थाओं द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। इन संस्थाओं के उपार्जन केन्द्रों द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं, धान आदि फसलों का उपार्जन किया जाता है। सहकारी संस्थाओं से प्रदेश में फसलों का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के समय में भी किसानों से एक करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 37 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था।

-मंत्री डंग ने दिया निवेशकों को सहायता का आश्वासन

मध्यप्रदेश में तीन नयी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं होंगी तैयार

» ऊर्जा सेशन में 16 हजार करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित

भोपाल। जागत गांव हमार

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने उद्योगपतियों को प्रदेश की नवकरणीय परियोजनाओं में निवेश करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नवकरणीय ऊर्जा के 500 गीगावाट के लक्ष्य की 50 प्रतिशत आपूर्ति की तैयारी मप्र कर रहा है। ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 7 हजार 500 करोड़ रुपए की 3 अन्य फ्लोटिंग परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साठ हजार मेगावाट की सोलर, 15 हजार मेगावाट की पवन एवं अन्य नवकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजना स्थापना की संभावना है। प्रदेश में अब तक 60 हजार मेगावाट से अधिक सोलर और लगभग 5 हजार मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना क्रियान्वित और क्रियान्वयन स्तर पर है। इनवेस्टर्स समिट में 128 औद्योगिक घरानों ने नवकरणीय ऊर्जा में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। यह जानकारी आज प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा संजय दुबे की अध्यक्षता में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नवकरणीय ऊर्जा पर हुए सत्र में दी गई।

जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया

सेशन में संस्थापक और सीईओ ओटू पॉवर प्राइवेट लिमिटेड पराग शर्मा ने मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसर पर प्रस्तुतिकरण दिया। एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट ग्रीनको ग्रुप प्रवीन मित्तर नंदा, अवाडा ग्रुप के अध्यक्ष विनीत मित्तल, एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक मोहित भार्गव, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ आशीष खन्ना, एसजेवीएन के सीएमडी नंदलाल शर्मा और आरईसी लिमिटेड के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसर, कठिनाइयां, चुनौतियां और समाधान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अपनी परियोजनाओं की जानकारी दी। सत्र के बाद जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया।

एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया की उपस्थिति में 16 हजार करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। इनमें से एक हजार करोड़ रुपए का एमओयू आरईसी एवं रम्स के मध्य और 15 हजार करोड़ का पीएमसीएल एवं आरईसी के मध्य हुआ।

निवेशकों ने जताई इच्छा

मध्यप्रदेश में पिछले साल के अंत में नवकरणीय ऊर्जा नीति, सुविधाएं और निवेशक फ्रेंडली वातावरण ने निवेशकों को राज्य की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी बनाई गई है। प्रदेश जल्द ही ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला राज्य बनने जा रहा है। इसमें भी उद्योगपतियों ने निवेश की रूचि दिखाई। मध्यप्रदेश ऐसा अकेला राज्य है जहाँ पर निकट भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट स्थापित होने वाले हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट से एक साल के भीतर बड़ा ग्रीन ऊर्जा उत्पादन शुरू होने वाला है।

20 हजार मेगावाट ऊर्जा का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 तक नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देते हुए 20 हजार मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025 तक 1400 मेगावाट का मुरैना और 950 मेगावाट का छतरपुर में हायब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज शुरू हो जाएगा। वहीं वर्ष 2023 सितंबर तक 600 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर-शाजापुर-नीमच परियोजना भी उत्पादन देने लगेगी।

गीला-सूखा कचरा के साथ रोटी-हरी सब्जी की अलग से जगह

खंडवा में नगर निगम ने कचरा वाहनों में लगवाए अलग से गौ-ग्रास के पात्र

खंडवा। जागत गांव हमार

गो-सेवा प्रकल्प के तहत खंडवा में नगर निगम ने पहल करते हुए कचरा वाहनों में गौ-ग्रास पात्र लगाए हैं। इसकी शुरुआत प्रारंभिक तौर पर 5 वार्डों के कचरा वाहनों से की है। इन वाहनों में गीला-सूखा कचरा के साथ अब दो अलग पात्र होंगे, जिसमे गाय के लिए रोटी व हरी सब्जियां अलग रखी जा सके। इस नवाचार के चलते पशुओं का खाने योग्य भोजन अलग हो जाएगा, जिसे हम और आप घर के बाहर सीढ़ियों पर रख देते हैं। महापौर अमृता यादव का कहना है कि, घरो से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग कर कचरा वाहन में देने की अपील की जाती हैं। दो अन्य बाक्स में खराब ट्यूब लाईट, बल्ब, रिमोट आदि तथा डायपर, सेनेटरी नेपकीन, मास्क रखे जाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि, घर से निकलने वाले भोजन की बची हुई खाद्य सामग्री एवं हरी सब्जियों का कचरा गाय को खिलाने के उद्देश्य से हम लोग घर के बाहर सीढ़ी के पास या नाली या फर्श पर रख देते है। जिसे बाहर घूमने वाले गौवंश खा लिया करते है। इनमें पॉलीथिन भी होती है, जो गाय के पेट मे जाने पर आंतों में फंसने से उसकी मौत का कारण भी बन जाती है। कई बार यह खाद्य सामग्री अधिक समय तक पड़ी रहती है, या सड़क/ नाली में गिर जाती है। जिससे सड़क पर झाड़ू लगने या कचरा वाहन द्वारा घरों से कचरा प्राप्त करने के बाद पुन: गंदगी होती है।

पांच वार्डों से शुरुआत

महापौर यादव के अनुसार शुरुआती तौर पर इन गौ-ग्रास पात्रों को 5 वाहनों में लगाया गया है। जो शहर के सुरज कुंड वार्ड क्रमांक 03, किशोर कुमार गांगोली वार्ड 5, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 23, सिंधु सम्राट दाहिर सेन वार्ड 37, लालबहादुर शास्त्री वार्ड 48, रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 38 से गौ-ग्रास एकत्र करेंगे।

गाय की रोटी के लिए अलग बाक्स

इस संवेदनशील विषय पर नगर निगम ने संज्ञान लेकर एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया है, अब कचरा वाहनों में दो अलग-अगल बाक्स गाय की रोटी और सब्जियों के लिए लगाए गए है। शहर की आम जनता अपने-अपने घरों से निकलने वाले गौ ग्रास को निगम के डोर टू डोर वाहन में लगे बाक्स में डालेंगे। निगम की गौशाला मे इसे गौमाता को खिलाया जाएगा, अब शहरवासी रोजाना गौ ग्रास के साथ ही गीला एवं सूखा कचरा भी नियमित रूप से देकर सहयोग करें। गाय के लिए रोटी तथा हरे खाद्य जैसे सब्जी-भाजी के अवशेष, खराब पत्तियां, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके आदि के लिए दो बॉक्स अलग-अलग लगाए गए हैं।

युवा किसान ने यूट्यूब से सीखा तरीका, अब कर रहे मुनाफे की पैदावार

मध्यप्रदेश के खेतों में भी पैदा हो रही स्ट्रॉबेरी

बड़वानी। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में युवा किसान खेती में इनोवेशन करके रिस्क लेकर नई-नई फसल उगाकर खूब लाभ कमा रहे हैं। इस सप्ताह बात करेंगे बड़वानी जिले के सेंधवा से 15 किमी दूर सालीटांडा गांव के युवा किसान हिमांशु डावर की, जो इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने 3600 वर्ग फीट के प्लॉट पर 2 हजार पौधे लगाकर 80 हजार रुपए मुनाफा कमाया है। स्ट्रॉबेरी की खेती उन्होंने यूट्यूब से सीखी है। आज वे हजारों कमा रहे हैं। किसान हिमांशु ने इस बार आधा बीघा जमीन में स्ट्रॉबेरी लगाई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की नर्सरी से स्ट्रॉबेरी के 6 हजार पौधे बुलाकर लगाए हैं। इस बार भी फसल अच्छी आई है। स्ट्रॉबेरी बाजार में 250 से 280 रुपए प्रति किलो भाव मिल रहा है। हिमांशु अभी स्ट्रॉबेरी को सेंधवा, राजपुर और बड़वानी में बेच रहे हैं।

हिमांशु डावर और उनके पिताजी 5 एकड़ खेती में पारंपरिक रूप से गेहूं, मक्का, कपास की खेती करते थे। इससे घर का गुजारा ही हो पाता था। साल में 40 से 50 हजार रुपए की उपज मुश्किल से बेच पाते थे। हिमांशु ने बताया कि वे सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं। पारिवारिक परिस्थिति और अन्य कारणों से आगे नहीं पढ़ पाए। उन्हें खेती का ही काम आता था। उन्हें पता चला कि चाचा स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। यह हिमांशु के लिए कुछ नया था। बाजार में तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी देखी थी, लेकिन इसकी खेती कैसे होती है, यह जानने के लिए वे खरगोन जिले के झिरन्निया तहसील में रहने वाले अपने चाचा संजय डावर के पास गए। उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जाना, लेकिन इतना समझ नहीं पाए। फिर यूट्यूब पर सर्च किया तो कई जानकारियां मिली।

गिलहरी, चिड़िया से नुकसान

स्ट्रॉबेरी को दिन में गिलहरी, चिड़िया और रात में उदबिलाव और कोलीया (जंगली जानवर) से बचाना पड़ता है। ये स्ट्रॉबेरी को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए रात में भी खेत में रोशनी करना पड़ती है। हिमांशु के खेत की स्ट्रॉबेरी बड़वानी, राजपुर, सेंधवा, नागलवाड़ी सहित अन्य क्षेत्र में पसंद की जाती है। बड़वानी, सेंधवा के कई डॉक्टर, मेडिकल, व्यवसायी और अन्य सीजन में सीधे संपर्क करते हैं।

नासिक-हिमाचल से मिला पौधा

हिमांशु डावर ने बताया कि नासिक के सापुतारा से भी पौधे मंगवाए थे, लेकिन एक पौधा 12 रुपए का पड़ रहा था, जो काफी महंगा था। इसके बाद यूट्यूब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की नर्सरी से संपर्क किया, वहां से एक पौधा 5 रुपए में मिला, जो ऑर्डर के एक दिन बाद इंदौर आ जाता है।

250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेच रहे

बाजार में स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए 250 ग्राम के पैकेट बनाते हैं। अभी क्षेत्र के कई लोग 10 से 15 पैकेट के ऑर्डर देते हैं। वर्तमान में लगाई फसल 10 दिन में आ जाएगी। हिमांशु अभी छोटे स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं। आने वाले समय पर इसे एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में करेंगे। स्ट्रॉबेरी के साथ खेत में करीब 700 पौधे संतरे के भी लगाए हैं।

सितंबर-अक्टूबर में बोवनी

स्ट्रॉबेरी की खेती सामान्य तौर पर पहाड़ी और ठंडे इलाकों में की जाती है। यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में होती है। कुछ साल से मप्र, महाराष्ट्र, उप्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इसकी बोवनी सितंबर और अक्टूबर में होती है। ठंडी जगहों पर फरवरी और मार्च में बोया जाता है। मप्र में खेती करने वाले किसान इसकी अक्टूबर अंत में बोवनी करते हैं।

पुश्तैनी जमीन पर मिर्च के पौधे उगाकर देशभर में कर रहे सेल

मिर्च की खेती से कमा रहे 15 लाख महीना

धार। जागत गांव हमार

खेती भी लाभ का धंधा है... इस वाक्य को मप्र के कई किसान सच साबित कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं धार के अनिल मुकाती। जिन्होंने मल्टी नेशनल कंपनी में 15 लाख के सालाना पैकेज की रीजनल मैनेजर की नौकरी छोड़कर सब्जी उगाने का बीड़ा उठाया। सब्जी उगाते-उगाते उन्होंने एक नया प्रयोग करते हुए मिर्च के पौधे उगाकर उसे बेचना शुरू किया। 5 साल में उनकी कमाई लाखों में पहुंच गई। आज अनिल अपनी 5 एकड़ पुस्तैनी जमीन पर करीब 1 करोड़ मिर्च के पौधे उगाकर देशभर में सेल कर रहे हैं। खास बात यह है कि भी खुद मैनेजर रहे अनिल के लिए आज 3 मैनेजर समेत 38 लोगों की टीम काम कर रही है। अनिल ने इंदौर के कृषि कॉलेज से 2002 में ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल का डिप्लोमा किया। इसके बाद एक कृषि कंपनी में रीजनल मैनेजर के पद पर काम करने लगे। फिलहाल वे अपने पिता मोहनलाल मुकाती, माता रुखमा मुकाती, पत्नी शीला मुकाती, बेटा भूमध्य मुकाती के साथ घर पर ही रहते हैं। इसके अलावा मुकाती का दूसरा भाई सुनील मुकाती डॉक्टर हैं।

राजस्थान के किसानों को देखकर जागी रुचि

अनिल ने बताया कि रीजनल मैनेजर रहते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का टूर लगता रहता था। जहां बड़े किसानों को मैं पॉलीहाउस से सब्जियों को तैयार करते हुए देखा करता था। मैंने किसानों से बात की तो पता चला कि वे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। 2017 में खेती को लाभ का धंधा बनाने के अभियान के तहत उद्यानिकी विभाग ने 10 किसानों के चयन की प्रक्रिया शुरू की। इसमें मैं भी शामिल हो गया। अभियान के तहत मुझे पॉलीहाउस बनाने के लिए सरकार की ओर से मदद के रूप में लोन दिया गया। इससे मैंने एक एकड़ जमीन में बीज रहित खीरे लगाए। 4 महीने में ही खीरे के पौधे तैयार हो गए। इसी तरह 4 महीने में ही मुझे 9 लाख का फायदा हो गया। इतना बड़ा फायदा देख मेरी और मेरे परिवार की रुचि खेती में और बढ़ गई।

ले रहे 30 लाख का फायदा

किसान अनिल ने कुल 7 हेक्टेयर जमीन में से 5 एकड़ पर पॉलीहाउस बना रखा है, जहां किसानों की मांग पर मिर्च के पौधे तैयार किए जाते हैं। उनका कहना है कि वह हमेशा अच्छे बीजों का ही यूज करते हैं। इसके बाद ऑर्डर अनुसार आस-पास के जिलों के साथ दूसरे प्रदेश में भी पौधे सप्लाई करते हैं। एक पौधा तैयार करने में करीब 1 रुपए 40 पैसे का खर्च आता है, जिसे वह 1 रुपए 70 पैसे में बेचते हैं। उन्हें हर पौधे पर 30 पैसे की बचत होती है। इसी तरह हर 2 महीने में 1 करोड़ पौधे बेचने पर उन्हें 30 लाख रुपए का फायदा होता है।

60 दिन में तैयार फसल

मेरे पॉलीहाउस से करीब 1 करोड़ मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों को तैयार होने में करीब 45 दिन लगते हैं। इसके बाद अगले 15 दिनों में पौधे किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद अगली सीजन की सब्जियों के लिए पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है।

इजराइली तकनीक का इस्तेमाल

पौधे तैयार करने में विशेष तौर पर तापमान का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें गर्मी के 4 महीनों से सितंबर तक पौधों की विशेष निगरानी करनी होती है। इसलिए तेज धूप से बचाने के लिए पॉलीहाउस की छत के नीचे ग्रीन नेट लगा रखी है, जिसे दिन में लगाते हैं, क्योंकि दिन का तापमान 42 के आसपास होता है। हालांकि पौधों के लिए 35 से 38 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। तापमान के लिए इजरायल में उपयोग होने वाले ऑटो मिशन फॉगर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे 12 लाख रुपए में इंदौर से खरीदा था। मशीन ऑटो सिस्टम के तहत तापमान के अनुसार चालू-बंद होती रहती है।

बेंगलुरु से मंगाते है खाद

अनिल ने बताया कि हमारे यहां पॉली हाउस की देखरेख के लिए 3 मैनेजर सहित 35 मजदूर काम करने आते हैं। उन्होंने बताया कि मिर्च के पौधे तैयार करने के बाद टमाटर और पपीते लगाए जाएंगे। पौधों के लिए बेंगलुरु से विशेष खाद मंगाई जाती है। पौधों की निगरानी के लिए पॉली हाउस में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं।

गुना में दोस्त के आइडिया ने बदली किस्मत

गुलाब की महक दुबई से बांग्लादेश तक पहुंच रही

गुलाब से रोज छह हजार रुपए कमा रहा किसान

गुना। जागत गांव हमार

गुना शहर के कोकाटे कॉलोनी में रहने वाले 27 साल के इंजीनियर अनिमेश श्रीवास्तव। भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी शुरू की। तभी किसी दोस्त के पॉली हाउस में पहुंचे। दोस्त के एक आइडिया ने उनकी किस्मत बदल दी। यहीं से उनका रिश्ता मिट्टी से जुड़ गया। उनके पॉली हाउस में लगाए गए गुलाब की महक दुबई और बांग्लादेश तक पहुंच रही है। वे रोजाना 5-6 हजार रुपए के गुलाब जयपुर और दिल्ली भेज रहे हैं। रोज 60-70 बंडल फूलों का उत्पादन हो रहा है। इंजीनियर अनिमेश श्रीवास्तव का कहना है कि मैंने पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी से 15 दिन की ट्रेनिंग ली। वहां मैंने किस किस्म की मिट्टी में कौन सी फसल बेहतर हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग ली। मैंने 2018 में गुना से 30 किमी दूर म्याना के पास अपनी जमीन पर खेती शुरू की। 3 एकड़ में मैंने पॉली हाउस बनाया और गुलाब की खेती शुरू की। पुणे के तलेगांव से डच रोज किस्म के पौधे मंगाए। देश में केवल यही एक ऐसी जगह है, जहां डच रोज के पौधे मिलते हैं। डच रोज का एक पौधा 11 रुपए में खरीदा। कुल 3 एकड़ में 24 हजार पौधे लगाए। 5 वर्ष तक यह पौधे लगातार उत्पादन देते हैं। पॉली हाउस बनाने में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए। इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली। 12-13 लाख रुपए का निवेश किया। मेरे गुलाबों का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली और जयपुर है। इसकी वजह है कि गुना से यहां ट्रांसपोर्ट आसान है। रोजाना ट्रेन से जयपुर और दिल्ली गुलाब भेजे जाते हैं। दिल्ली के कुछ व्यापारी यहां से गुलाब खरीदकर दुबई और बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट करते हैं।

ऐसी जलवायु चाहिए

पौधे लगाने से पहले बेड बनाए जाते हैं। 90 सेमी चौड़े और एक से डेढ़ फुट ऊंचे मिट्टी के बेड के बीच की दूरी 40 सेमी रखी जाती है। बेड बनाते समय गोबर का खाद या ऑर्गेनिक खाद डाला गया। बेड बन जाने के बाद हाथ से एक-एक कर पौधे रोपे जाते हैं। एक पौधे से दूसरे की दूरी 15 सेमी रखी जाती है। डच रोज के लिए 25-27 डिग्री तापमान और 70-85 प्रतिशत नमी की जरूरत होती है। एक बार तोड़ने के 40 दिन बाद फिर फूल खिल जाते हैं। यह क्रम पूरे साल चलता रहता है।

60-70 बंडल रोज होता है उत्पादन

एक दिन में 60-70 बंडल गुलाब का उत्पादन होता है। एक बंडल में 20 गुलाब रहते हैं। बंडलों में पैक करके ही इसे आगे भेजा जाता है। एक बंडल की कीमत एवरेज 100 रुपए तक होती है। कभी यह कम भी होती है, लेकिन सीजन के दौर में ज्यादा कीमत भी मिलती है।

ऐसे होती है सिंचाई

सिंचाई के लिए ड्रिप एरिगेशन का इस्तेमाल होता है। दो पाइप लगाए जाते हैं। एक पाइप से पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरे पाइप से पत्तियों और डालियों को पानी मिलता है। पॉली हाउस के बाहर एक पानी का टैंक बनकर उससे सप्लाई होती है। यह ध्यान रखा जाता है कि पानी ज्यादा न हो। ऐसा होने पर बेड के टूटने का खतरा होता है। पानी कम भी न हो, नहीं तो पौधे सूख सकते हैं। फिर रोजाना पौधों पर कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम का छिड़काव किया जाता है।

सीएम शिवराज ने निवेशकों से चर्चा के दौरान कहा

कृषि उत्पादों का बादशाह मप्र

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर कृषि क्षेत्र में निवेश के इच्छुक इंवेस्टर्स से चर्चा की। कई इन्वेस्टर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में कृषि उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने करने पर विचार कर रहे हैं। इंवेस्टर्स से मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को सरकार विशेष प्रोत्साहन देगी। इन क्षेत्रों में पिछले 15 सालों में अनेक नई इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। चौहान ने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश के नए प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य शासन पूरा सहयोग प्रदान करेगा। मुलाकात करने वालों में अविगना प्राइवेट लिमिटेड के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर अभिजित वर्मा, सीबीआरई के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन चंद्रा और एक्सिस बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट इलयास इकबाल शामिल थे।

मप्र सोया राज्य

देश के कुल सोयाबीन का 48 प्रतिशत उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है। यहां इससे जुड़े काम के लिए निवेश किया जा सकता है। पूरे देश में मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं ने अपनी मिठास, पौष्टिकता और चमक के कारण अलग पहचान बनाई हुई है। इस गुणवत्ता का गेहूं और कहीं नहीं मिलता।

कृषि क्षेत्र में कहां है मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सोयाबीन एवं दलहन उत्पादन में काफी आगे है। यह चना, उड़द, तुअर, मसूर, अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान एवं मक्का, तिल एवं मूंग के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है. गेहूं, ज्वार, जौ के उत्पादन में देश में तृतीय स्थान पर है।

मप्र में कृषि का रकबा

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 307.56 लाख हेक्टेयर में से लगभग 151.91 लाख हेक्टेयर में कृषि कार्य होता है। मध्य प्रदेश में कृषि से जुड़े व्यवसाय मुख्य रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। इसलिए यहां कृषि क्षेत्र में निवेश की काफी संभावना है।

इन क्षेत्रों में निवेश की संभावना

मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों में चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम तथा वनस्पति घी प्रमुख है। राज्य में तिलहन एवं सोयाबीन की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसकी वजह से यहां वनस्पति घी बनाने वाली मिलों की संख्या काफी हैं। ऐसे कारखाने तिलहन उत्पादक क्षेत्रों मालवा पठार, मध्य नर्मदा घाटी एवं चंबल घाटी क्षेत्र में हैं।

स्टैकिंग, येलो, ब्लू स्ट्रीप में टमाटर में एकीकृत कीट प्रबंधन

किसानों को कृषि वैज्ञानिक कर रहे जागरुक

जानकारी के अभाव में टमाटर उत्पादकों को होता है घाटा

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा विगत दिवस ग्राम पराखास के किसानों के प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान जगदीश अहिरवार ग्राम पराखास के द्वारा टमाटर प्रजाति काशी अभिमान स्टैकिंग विधि से वैज्ञानिकों के सलाह एवं तकनीकी से लगायी गयी है। टमाटर की बहुत सी किस्में अलग-अलग कम्पनियों एवं आईसीएआर, आईआईएचआर, बैंगलोर द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली और त्रिगुणित रोगरोधी किस्में अर्कारक्षक एवं अर्कासम्राट विकसित की है, लेकिन किसान को उत्पादन तकनीक की सही जानकारी का आभाव होने के कारण या समय पर कीट-व्याधियों का उचित प्रबंधन न करने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है। टमाटर की रोपणी तैयार कर रोपाई से पहले फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम+मेकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ो को उपचरित करने के साथ ही रबी मौसम में टमाटर के फलों के उत्तम व आकर्षक रंग, सड़ने से बचाने, फलों को उचित आकार के लिए सहारा देना आवश्यक होता है। चूंकि टमाटर का पौधा शाकीय होता है, इसलिए लदे हुए फलों का भार सहन नहीं कर पाता है। जब हम सिंचाई करते हैं तो नमी के कारण फल सहित इसकी शाखाएं जमीन पर गिर जाती हैं। यदि पौधों को सहारा न दिया जाए तो फल मृदा के संपर्क में आने पर सड़ जाता है। फल गुणवत्ताहीन हो जाता है। इससे बाजार

मूल्य में गिरावट हो जाती है। डॉ. बीएस किरार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख ने बताया कि टमाटर में पत्ताधब्बा व फलसड़न, लघुपत्र रोग उकठा या म्लानि जीवाणु रोग ज्यादा फसल को हानि पहुंचाते हैं। पत्तीधब्बा व फलसड़न से पौधों की पत्तियों पर भूरे रंग के गोल एवं अनियमित आकार के धब्बे एवं इन पर काले रंग की बिन्दू के समान फफूंदी संरचनाएं दिखाई देती हैं।

सड़ने लगते हैं फल| फलों में गड्ढेदार धब्बे व फल सड़ने लगते हैं। लघुपत्र रोग से ग्रसित पत्तियां अत्याधिक छोटी और समूह में दिखाई देती है। पौधों में फूल नहीं लगते हैं। म्लानि जीवाणु रोग से अचानक पौधे मुरझा कर सूख कर मर जाते हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन और बीज और रोपणी का फफूंदनाशक दवा मेंकोजेब 3 ग्रा. प्रति लीटर पानी के घोल से उपचार कर रोपाई करें। चूषक कीटों से बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स या डाइमेथोएट या इमिडाक्लोप्रिड दवाओं का छिड़काव करें।

दवा का करें छिड़काव

फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए फ्लूबेन्डामाइड 20 प्रतिशत डब्ल्यूजी दवा का छिड़काव करें। साथ ही टमाटर में कीट नियंत्रण के लिए किसान येलो एवं ब्लू स्ट्रीप का प्रयोग करें। येलो एवं ब्लू स्ट्रीप के अंदर चिपकने जैसा तरल पदार्थ होता है। कीट आकर्षित होकर येलो एवं ब्लू स्ट्रीप की तरफ आने लगते हैं, जैसे ही वो इसके सम्पर्क में आते हैं तरल पदार्थ के कारण चिपक जाते हैं।

कतार में लगे टमाटर को बांधे

डॉ. एसके सिंह वैज्ञानिक उद्यानिकी ने बताया यदि किसान टमाटर की खेती सहारा देकर (स्टेकिंग) पद्धति से नहीं करते हैं तो पैदावार में लगभग 30-35प्रतिशत प्रति हेक्टेयर कमी आ जाती है। हमारे जिले के जो भी किसान टमाटर की खेती व्यवसायिक स्तर पर करना चाहते हैं, वे सहारा देने के लिए टमाटर जिस कतार में लगे हैं, उस कतार में 5 मीटर के अंतराल पर 2 मीटर ऊंचे बांस लगा देते हैं फिर इन बांसों में 3-4 पतले तार इस प्रकार से बांधते हैं कि पहला तार जमीन से लगभग 45 सेमी ऊंचाई पर रहे। शेष तार 30-30 सेमी. की ऊंचाई पर इस तरह बांधते हैं कि एक मंडप जैसी आकृति बन जाए। इन तारों में सुतली बांधकर सुतली के नीचे जाने वाले छोर पर छोटी-छोटी खुटियां बांधकर उस खूटी के पौधे के बगल में लगा देते हैं जिससे पौधे सुतली के सहारे ऊपर चढ़ सके।

प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें किसान- डॉ. सिंह

लहार। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक खेती परियोजना अंतर्गत रौन ब्लॉक के मानगढ़ गांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्राकृतिक कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मानगढ़ सहित आसपास के गांवों के प्रगतिशील किसानों ने भाग लेकर प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझा।

संगोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ एस पी सिंह ने कहा कि प्राकृतिक कृषि अपनाने से किसानों की लागत में कमी आएगी तथा तथा समाज में फैल रहीं प्राण घातक बीमारियों से बचा जा सकेगा। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों युक्त खेती कैंसर जैसे प्राणघातक रोग फैलाकर लोगों की जान ले रही है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्राकृतिक कृषि देशी गाय आधारित खेती है। एक देशी गाय से किसान 30 एकड़ भूमि पर बड़ी आसानी से प्राकृतिक कृषि कर सकते हैं। प्राकृतिक कृषि में देशी गाय के गोमूत्र और गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि बनाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक कृषि से किसानों की लागत में काफी कमी आती है। वही प्राकृतिक कृषि से पैदा उत्पाद स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। बाजार में प्राकृतिक कृषि के माध्यम से पैदा किए गए कृषि उत्पादों से दुगनी कीमत किसानों को प्राप्त हो सकती है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह प्राकृतिक कृषि की दिशा में आगे बढ़े और इसे अपनाएं। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ अवधेश सिंह ने बताया कि देशी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। जिन किसानों के पास देशी गाय नहीं है, ऐसे किसान आवारा, घुमंतू देशी गाय को पकड़कर उसका गोमूत्र और गोबर इकट्ठा कर सकते हैं।

-किसानों को करना होगा गौवंश का पालन

प्राकृतिक कृषि आज की आवश्यकता

बैतूल। कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 10 विकासखंडों के 280 कृषकों, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के बीच एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें अतिथि के रूप में डॉ. व्हीके पराडकर, अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, छिंदवाड़ा शामिल हुए। डॉ. पराडकर द्वारा कृषकों से आह्वान किया गया कि प्राकृतिक कृषि करने के लिए गौवंश का पालन एवं संकर प्रजातियों के स्थान उन्नत बायोफोर्टीफाइड प्रजातियों को लगाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश्वर सिंह चंदेल, अध्यक्ष किसान मोर्चा के साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। चंदेल द्वारा कृषकों से निवेदन किया गया कि वे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें जिससे सभी को लाभ मिल सके।

किसानों को दिया प्रशिक्षण

केन्द्र की वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे द्वारा प्राकृतिक कृषि के विभिन्न आयामों पर कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। सजीव प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। शैक्षणिक प्रक्षेत्र पर प्राकृतिक कृषि के प्रदर्शन भूखंडों का भ्रमण वैज्ञानिक आरडी बारपेटे द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. एमपी इंगले, खाद्य विशेषज्ञ द्वारा किया गया।

प्राकृतिक कृषि प्रदर्शनों के लाभार्थी कृषकों को विभिन्न जैव घटक बनाने के लिए प्लास्टिक के 200 लीटर क्षमता के ड्रम माननीय अतिथियों के द्वारा प्रदान किए गए। कार्यक्रम के आरंभ में केन्द्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. व्हीके वर्मा द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया एवं प्राकृतिक कृषि के महत्व को रेखांकित किया।

किसान यूरिया का छिड़काव सुबह या रात में नहीं करें

रबी फसलों के विपुल उत्पादन के लिए किसानों को दी सलाह

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह द्वारा रबी फसलों के विपुल उत्पादन के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को समसमायिकी सलाह दी गई।

गेहूं की फसल- गेहूं की फसल में द्वितीय सिंचाई बोवनी के 40-45 दिन बाद कल्ले निकलते समय करें। समय से बोई गई फसल में तृतीय सिंचाई बोवनी के 60-65 दिन बाद तने में गांठे बनते समय करें।, गेहूं मे यूरिया का उपयोग सिंचाई उपरान्त ही करें। जिससे कि नत्रजन का समुचित उपयोग हो सके। यूरिया को छिड़काव सुबह या रात में न करें। क्योंकि ओस की बूंदों के सम्पर्क में यूरिया आने से पौधे की पत्तियों को जला देती है। फसल से औस हटने पर दिन के समय यूरिया का दूसरा छिड़काव गमोट अवस्था में 20 से 30 किग्रा प्रति एकड़ किस्म के अनुसार करें।

चना की फसल- चने के खेत में कीट नियंत्रण के लिए टी आकार खूटियां (14-15/एकड़) लगाएं और फली में दाना भरते समय खूंटियां निकाल लें। चने की फसल में चन की इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर (1-2 लार्वा/मी. पंक्ति) से अधिक होने पर इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा फ्लूबेन्डामाइड 39.35 एससी की 40 मिली/एकड़ या इन्डोक्साकार्ब 15.8 ईसी की 14 मिली/एकड़ का 150-200 ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

सरसों की फसल| सरसों में सिंचाई, जल की उपलब्धना के आधार पर करें। यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50-60 दिनों की अवस्था पर करें। दो सिचांई उपलब्ध होने की अवस्था में पहली सिंचाई बुवाई के 40-50 दिनो के बाद एवं दूसरी 90-100 दिनों बाद करें। यदि तीन सिंचाई उपलब्ध है तो पहली 30-35 दिन पर व अन्य दो 30-35 दिनो के अंतराल पर करें। बुवाई के लगभग 2 माह बाद जब फलियों में दाने भरने लगे उस समय दूसरी सिंचाई करें। तापमान में तीव्र गिरावट के कारण पाले की भी आशंका रहती है। इससे फसल बढ़वार और फली विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए सल्फर युक्त रसायनों का प्रयोग लाभकारी होता है।

मटर की फसल

मटर की फसल की पत्तियों पर धब्बे दिखाई दे तो मेन्कोजेब 75: डब्ल्यू पी. फफूंदनाशी का 2 ग्रा. या कार्बेन्डाजिम 12: मेन्कोजेब 63: डब्ल्यू पी फफूंदनाशी के मिश्रण का 2 ग्रा/ली पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की फसल में चूर्णिल फफूदी रोग के लक्षण जैसे पत्तियों, फलियों एवं तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए फसल पर सल्फेक्स 3 ग्रा./ली. पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

मसूर की फसल

फसल पर एनपीके (19:19:19) पानी में घुलनशील उर्वरक को फूल आने से पहले और फली बनने की अवस्था पर 5 ग्रा./ली पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि उपज में वृद्धि हो सके। फसल पर माहू कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डायमिथोएट 30 ईसी 2 मीली/ली या इमिडाक्लोप्रिड 0.4 मिली/लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

गन्ना की फसल- शीतकालीन गन्ने की फसल में गुडाई करें। खेत में नमी की कमी होने पर सिंचाई कर सकते हैं।

नई तकनीक का उपयोग कर संयुक्त कार्य करेंगे

कृषि क्षेत्र में मिल कर कार्य करेंगे एमपी-गुयाना

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति डॉ. अली से मध्यप्रदेश और गुयाना के मध्य द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार-उद्योग क्षेत्र में मिलकर कार्य किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली को मध्यप्रदेश की जनजातीय चित्रकला की कृतियां भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति डॉ. अली की मध्यप्रदेश में कृषि, सिंचाई क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास की जानकारी दी। राष्ट्रपति डॉ. अली ने एक करारनामा करने पर सहमति जताई, जिसमें मध्यप्रदेश और गुयाना फूड प्रोसेसिंग, कृषि और सिंचाई क्षेत्र में पार्टनर होंगे। इन क्षेत्रों में नवीन तकनीक का उपयोग कर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति संतोखी को दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति संतोखी को मप्र की चित्रकला और वस्त्र-कला के नमूने भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरीनाम और गुयाना दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से सार्थक चर्चा हुई है। बड़े औद्योगिक संस्थानों से दोनों देशों का संपर्क करवाया जाएगा, जिससे ठोस परिणाम सामने आए।

जेएलएल समूह ने मप्र में करेगा रुचि

मुख्यमंत्री से वैश्विक स्तर पर कमर्शियल रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्यरत जेएलएल समूह के संदीप पटनायक तथा मोहित जैन ने भेंट कर 5 हजार करोड़ के निवेश से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एवं इण्डस्ट्रियल पार्क की परियोजना का प्रस्ताव रखा। परियोजना के लिए विदेश एवं घरेलू संस्थाओं से वित्त पोषण लाने पर भी चर्चा हुई। नर्मदा शुगर प्रायवेट लिमिटेड के विवेक माहेश्वरी तथा अखिलेश गोयल ने प्रदेश में 450 करोड़ के निवेश से एथनॉल प्लांट, कंप्रेस्ड बॉयोगैस प्लांट और राइस ब्रान रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में चर्चा की।

स्ट्राबेरी-ब्लू-बेरी उत्पादन के प्रस्ताव

मुख्यमंत्री से वन-टू-वन चर्चा में कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड के पंकज ओस्टवाल ने झाबुआ में 200 हेक्टेयर भूमि पर 5100 करोड़ के निवेश से उर्वरक और कृषि रसायन की 7 इकाइयों की स्थापना संबंधी कार्य-योजना पर बातचीत की। टेक्समो पाइप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के संजय कुमार ने पीथमपुर में 130 करोड़ की लागत से 18 एकड़ भूमि पर एथनॉल संयंत्र की परियोजना की जानकारी दी। आबूधाबी की ई-20 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के परमेन्द्र गर्ग ने स्ट्राबेरी, ब्लू-बेरी की खेती, उनके प्र-संस्करण तथा वैश्विक स्तर पर वितरण के संबंध में प्रस्ताव दिया। भौगोलिक रूप से अनुकूल भूमि आवंटित करने का निवेदन किया।

प्रदेश में निवेश की अमृत वर्षा

- नव करणीय ऊर्जा- 6 लाख करोड़
- अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर - 2 लाख 80 हजार करोड़
- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण- एक लाख करोड़
- खनिज आधारित उद्योग क्षेत्र- एक लाख करोड़
- आई एवं इलेक्ट्रॉनिक्स- 78 हजार करोड़
- रसायन एवं पेट्रोलियम सर्विस सेक्टर - 77 हजार करोड़
- ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग- 42 हजार करोड़
- फार्मा एंड हेल्थकेयर-18 हजार करोड़
- लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग-18 हजार करोड़
- टैक्सटाइल एंड गारमेंट-17 हजार करोड़
- अन्य- एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए

टेक्समो इथिलीन लिक्विड का उद्योग

आठ सौ लोगों को मिलेगा रोजगार

बुरहानपुर में एक और नए उद्योग की उम्मीद

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

टेक्समो पाइप प्रोडक्ट प्रालि कंपनी के एमडी उद्योगपति संजय अग्रवाल भी बुरहानपुर में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इंदौर में आयोजित समिट में जब उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को अपना इथिलीन फ्यूल लिक्विड इंडस्ट्रिज का प्रोजेक्ट बताया, तो उन्हें बहुत पसंद आया। सीएम ने तुरंत अपने अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द जमीन तलाश कर इन्हें दी जाए। इस आश्वासन से प्राचीन शहर बुरहानपुर में एक और नए उद्योग की उम्मीद जग गई, जिससे बुरहानपुर के करीब 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्समो पाइप के संचालक संजय अग्रवाल ने कहा कि इन्वेस्टर समिट बहुत बढ़िया रहा। हमने समय लिया था फिर मुख्यमंत्री को हमारा पूरा 150 करोड़ का प्रोजेक्ट समझाया गया। उनका अच्छा रिस्पोंस रहा, पूरा कार्यक्रम अच्छा रहा। हमने उनसे कहा कि हमें 30 एकड़ जमीन इस इंडस्ट्रिज के लिए लगेगी, ये जमीन आप हमें लीज पर दें या सस्ती दर पर उपलब्ध कराएं। बुरहानपुर या पीथमपुर में जमीन मांगी। हमारी पहली प्राथमिकता बुरहानपुर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने अफसरों को जमीन तलाशने के निर्देश दिए। जल्द वे जमीन उपलब्ध कराएंगे और जो भी संसाधन सुविधाएं होगी देंगे।

प्रतिदिन 6 लाख लीटर पानी की जरूरत

इथिलीन फ्यूल लिक्विड फसलों के अपशिष्ट सड़े गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल और गन्ने के कुचे सहित अन्य अवशेषों से बनती है। इसकी जिले में बहुतायत है। प्रतिदिन छह लाख लीटर पानी की जरूरत लगेगी। इसके लिए ताप्ती नदी का पानी भी उपलब्ध है।

अभी 1200 लोगों के हाथों को दिया काम

उद्योगपति संजय अग्रवाल की वर्तमान में टेक्समो पाइप फैक्ट्री देश दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी वे इस उद्योग के माध्यम से 1200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नई इंडस्ट्री खुलने से 500 से 800 लोगों को रोजगार देंगे।

देशभर में होगा बुरहानपुर का नाम

संजय अग्रवाल बताते हैं कि इथिलीन लिक्विड का उद्योग यहां डलने से देशभर में बुरहानपुर का नाम होगा। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल और भारत पेट्रोलियम इसे खरीदेंगी। इसका उपयोग पेट्रोल-डीजल में मिलाकर ईंधन के रूप में होगा। क्योंकि केंद्रीय सडक़ परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने फैसला लिया है कि इस साल से पेट्रोल-डीजल में 15 प्रतिशत और अगले साल 20 से 25 प्रतिशत इथिलीन लिक्विड मिलाई जाएगी। इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी ही साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। यह उद्योग डलने से देशभर से लोगों का बुरहानपुर आना जाना रहेगा। इससे यहां अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार बढ़ेगा। यहां प्राचीन शहर बुरहानपुर में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला ने कहा-

खेती से मुनाफा कमाने तकनीकी से रूबरू हों किसान

भिंड। जागत गांव हमार

खेती बाड़ी में आज नई तकनीकी आ रही हैं। कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि शोध संस्थानों द्वारा नवीनतम तकनीकियों का विकास किया जा रहा है। किसानों को चाहिए कि वह कृषि की नवीनतम तकनीकी से रूबरू हों, जिससे खेती से मुनाफा कमाया जा सके। यह बात राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर के कुलपति डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला ने कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किसानों तक तकनीकी पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्रों के ऊपर है। इसलिए केंद्र के वैज्ञानिकों को नवीनतम कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी आदि तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है।

सराहना भी की

केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र के वैज्ञानिकों को केंद्र के फार्म में मोटे धान की खेती करने, पानी तथा मिट्टी की जांच कराने, फल वृक्षों में बेर तथा ऑवला का पौधरोपण कराने, मेड़ो पर करौंदा और बांस लगाने के सुझाव देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों की सराहना की गई। इस अवसर पर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा उन्हें केंद्र पर चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया

ड्रोन तकनीकी अपनाएं

शुक्ला ने कहा कि किसान उन्नतशील बीजों, नवीनतम कृषि यंत्रों, ड्रोन तकनीकी, नैनो यूरिया आदि का समावेश अपनी खेती बाड़ी में करते हुए खेती को और अधिक उन्नत एवं लाभप्रद बना सकते हैं। किसानों को चाहिए कि वह नवीनतम तकनीकी का लाभ उठाने के लिए आगे आएं। खेती में जंगली एवं आवारा जानवरों से हो रहे नुकसान की समस्या से बचाव के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि किसान अपने खेतों की मेड़ों पर चारों तरफ करौंदा तथा बांस के सघन पौधे लगाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)